

पत्र सं. 6/12/राज-6/99/30-अधिमुक्त-1-23

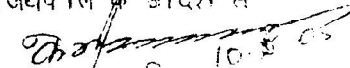
जयपुर, दिनांक:- 13.10.2005

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 & 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15 का धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं. प. 6/12/राज-6/99/30 दि. 18.9.99 को अतिरिक्त supersede करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा आदेश देती है कि आधिमुक्त सरकारी भूमि:-

1. विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उप-केन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए राज0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि0, राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमि0, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 जोधपुर को,
2. कार्यालय, बस अड्डा, डिपो और कारखाना के सन्निर्माण के लिए राज0 राज्य ग्रन्थि निगम को,
3. राजस्थान राज्य भंडारण निगम, राज. सहकारी दुग्ध उद्योग परिषद को:  
निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर आवंटित की जा सकेंगी:  
निबंधन और शर्तें

1. भूमि 99 वर्ष के बढ़ते पर दो जावेगी, जो 99 वर्ष की और कानाबन्धि के लिए नवीनीकरणीय होगी।
2. ऊपर लिखित विभाग/निगम/संस्था को आवंटित भूमि के संबंध में प्रौढियम का लें, क्लेक्टर द्वारा निर्धारित पडौस को उसी भूमि वर्गीकरण की कृषि भूमियों को आवंटन के समान विद्यमान कोमतों के समान होंगे किन्तु विद्युत निगमों को आवंटित भूमियों को इस हेतु देय राशि, राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता/सब्सिडी के रूप में समायोजित की जावेगी।
3. उर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.1.02 के अनुसार, दि. 18.1.02 से पूर्व की, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत निगम लि. जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध भूमि कोमत इत्यादि की बकाया राशि वसूल योग्य नहीं होगी। राजस्व लेखों में कायम ऐसी राशि को नियमानुसार राजस्व लेखों से कम लिया जावेगा परन्तु, यदि पहले से ही ऐसी कोई राशि वसूल कर ली गई है तो उसका प्रतिदाय रिफण्ड नहीं किया जायेगा। दि. 18.1.02 के बाद की विद्युत निगमों के विरुद्ध बकाया राशि विद्युत निगमों से वसूली योग्य है जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता/सब्सिडी के रूप में समायोजित की जावेगी।
4. किराया या नगरीय निर्धारण, शर्तें 10-2 में उल्लेखित राशि का 10% वृद्धि होगा, जो दस रुपये के निकटतम पूर्णांकित किया जायेगा।
5. इन प्रकार आवंटित भूमि, सिवाय उस प्रयोजन के जिसके लिये इसे आवंटित किया गया है, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जायेगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसका विक्रय नहीं किया जायेगा। परन्तु इस अधिसूचना के अधीन 2.08.1984 से 24.09.94 तक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किये गये भूमि आवंटन को कक्षा में प्रौढियम, बढ़ता किराया या शोधन नगरीय निर्धारण, यदि कोई हो, वसूल नहीं किया जायेगा, किन्तु पहले से ही वसूल कर ली गई ऐसी किसी रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

  
उप राज्य मंत्री